RNI Title-Code :- RAJBIL27027

www.nagaurdaily.com

Email. nagaurdaily0@gmail.com

नागौर डेली न्यूज

नागौर, कुचामनसिटी, डीडवाना, मकराना, परबतसर, जायल
मेड़तासिटी, खींवसर, डेगाना व नावां से एक साथ प्रकाशित

अहसास बदलाव का...

वर्षः 1 | अंक 168 | नागौर, 19 मई, 2022 (गुरूवार) | मूल्य 5 रुपया | पृष्ठ 4 | E-Edition

जयपुर के जुवेनाइल जेल में युवक का मर्डर

नाबालिग अपराधियों ने सोते समय रॉड से किया हमला, नींद में ही मार डाला

जयपुर.

जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाल सुधार गृह में नाबालिग अपचारियों (सजा काट रहे बच्चे) ने 20 साल के युवक की हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात की है। कुछ बच्चों ने एक साथ होकर सोते समय बंटी उर्फ सोनू पर हमला कर दिया। लोहे के रॉड से युवक पर कई वार किए। इससे उसकी नींद में बिस्तर पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को फिलहाल बंद कर दिया है। मरने वाला युवक भी कई मामलों में सजा काट रहा था। आगे बढ़ने से पहले इस गंभीर घटना पर अपनी राय जरूर दीजिए।

अब तक की जांच में सामने आया कि हमले के दौरान सोनू अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे कुछ किशोर कमरे में आए और उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सुबह करीब 7 बजे चौकीदार ने जब कमरे में शव देख पुलिस कंट्रोल रूम और बाल सुधार गृह के अधीक्षक को जानकारी दी।

मौके पर पहुंची पुलिस को सोनू के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने बाल सुधार गृह के अधिकारियों को मौके पर बुलाया है। बाल सुधार गृह में कुल 40 बच्चे बताए जा रहे हैं। हत्या करने वाले सभी बच्चे बाल सुधार गृह के अंदर ही हैं। उनकी जानकारी जुटाई जा रही है।

सरकारी टीचर्स ने खोला मोर्चा

जल्दी जारी हो ट्रांसफर लिस्ट, नहीं तो सीएम हाउस का करेंगे घेराव

जयपुर.

राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रदेश स्वच्छता पर पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने बताया की सरकार बने तीन साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स का अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं 9 महीने पहले जो आवेदन मांगे गए थे, उन्हें भी निरस्त करने की तैयारी है। ऐसे में अगर सरकार नए टीचर्स की ट्रांसफर लिस्ट नही निकली। तो प्रदेशभर के टीचर्स जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना देने के साथ ही सीएम हाउस का घेराव करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मंगलवार को कहा था कि शिक्षा विभाग ने टीचर्स के ट्रांसफर के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। जिसे शिक्षा विभाग ने अप्रूवल के लिए मुख्य सचिव को भेज दी है। ऐसे में नई पॉलिसी अप्रूव होने के बाद ने सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे जाएगे।

शिवराज सरकार को बड़ी राहत, मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव

नई दिल्ली।

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान लिया है।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है...सत्यमेव जयते। यह फिर से सिद्ध हो गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, मैं एससी को धन्यवाद देता हूं।

दिल्ली के उपराज्यपाल बैजल ने अचानक दिया इस्तीफा

नई दिल्ली.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मार्च 2022 से ही उनके हटने की अटकलें लगाई जा रही थीं। दिल्ली में नए उपराज्यपाल की रेस में प्रफुल्ल पटेल (प्रशासक, दमन-दीव) राजीव महर्षि (पूर्व गृह सचिव) का नाम सबसे आगे है। अनिल बैजल दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल बनाए गए थे। वे इस पद पर 5 साल से ज्यादा समय तक रहे। बैजल ने आज अचानक अपना इस्तीफा प्रेसिंडेट को भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी वजहों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है।

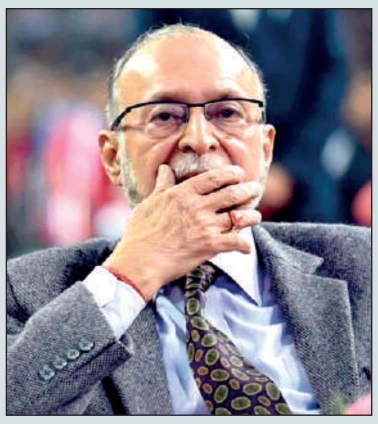

केजरीवाल से तकरार के कारण भी सुर्खियों में रहे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बैजल के बीच कई बार फैसलों को लेकर टकराव देखा गया। इस साल की शुरुआत में जब कोरोना जोर पकड़ रहा था, तो वीकेंड कर्फ्यू और सभी दुकानों के लिए ऑड-ईवन के नियम को लेकर दोनों आमने-सामने आ गए थे। बैजल ने केजरीवाल के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, दोनों के बीच दिल्ली में 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया पर भी तकरार देखने को मिली। बैजल ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, विजिलेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल थे। इसको लेकर भी विवाद हुआ था।

निजी कारणों का दिया हवाला

मुंडका अग्निकांड को लेकर एलजी ने दिए हैं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश-बता दें कि दिल्ली में 13 मई, 2022 को भयावह त्रासदी हुई थी। इसमें 27 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इस हादसे पर एलजी अनिल बैजल ने अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच को मंजूरी दी थी। इसे छह सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट (पश्चिम) संबंधित विभागों और एजेंसियों की ओर से चूक की जांच करेंगे।

कोरोना के समय दिखे थे काफी सख्त-दिल्ली में कोरोना के समय अनिल बैजल काफी एक्टिव होकर अधिकारियों की बैठक कर लोगों की सुरक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए थे। जब पूरे देश सहित दिल्ली में आक्सीजन की दिक्कत हुई थी तब उन्होंने अस्पतालों में हालात को बेहतर बनाने के लिए काफी निर्णय लिए जिससे लोगों को काफी सहूलियत हुई थी।

राजीव गांधी की हत्या का दोषी पेरारिवलन रिहा

नयी दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। वह 31 साल तक जेल में रहे और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर रिहा हुए। 9 मार्च को शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन को 30 साल से अधिक समय तक जेल में रखने और पैरोल पर बाहर होने पर शिकायतों का कोई इतिहास नहीं होने पर ध्यान देते हुए जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारिवलन की रिहाई पर राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से बंधे थे, और उनकी कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया, राष्ट्रपति को दया याचिका भेजकर कहा कि वह संविधान के खिलाफ किसी चीज से आंखें बंद नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया था कि अदालत को राष्ट्रपति के इस मुद्दे पर फैसला करने तक इंतजार करना चाहिए।

अदालत ने केंद्र को बताया था कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं, जबकि केंद्र को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।केंद्र ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया था। कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक ए जी

पेरारिवलन द्वारा दायर उम्रकैद की सजा को माफ करने की याचिका पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में सार्वजनिक बातचीत में पेरारिवलन की रिहाई की मांग जोरदार ढंग से उठी है। पेरारीवलन द्वारा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पत्र लिखकर उन्हें राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें छूट देने के फैसले के बारे में याद दिलाने के बाद हैशटैग #ReleasePerarivalan सोशल मीडिया में फैल गया, जो कि राजभवन में 16 महीने से अधिक समय से लंबित है। चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में बंद पेरारिवलन ने 25 जनवरी को राज्यपाल को पत्र लिखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 29 साल पहले हत्या के पीछे की बड़ी साजिश की जांच में प्रगति करने में विफल रहने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई थी।

हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी

हाईकमान का ध्यान मुद्दे सुनने से ज्यादा मोबाइल और चिकन सैंडविच पर : पटेल

अहमदाबाद.

गुजरात में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। पटेल पिछले एक महीने से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। वहीं 21 अप्रैल को भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के संकेत भी दिए थे। हार्दिक ने सोनिया गांधी को लेटर लिखते हुए कहा है कि कांग्रेस हाईकमान का ध्यान मुद्दे सुनने से अधिक चिकन सैंडविच और मोबाइल फोन पर रहता है।

चर्चा के दौरान नेताओं का ध्यान मोबाइल पर-हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देने के साथ ही सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है। पटेल ने कहा है कि हाईकमान मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जब मैं गुजरात की समस्याओं को लेकर जाता था, तो टॉप लीडरशिप मोबाइल फोन में व्यस्त रहते थे। वहीं हार्दिक के लेटर को कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा का एजेंडा बताया है।

राहुल ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था-हार्दिक पटेल की नाराजगी के बाद कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हुआ था। राहुल गांधी ने हार्दिक से मैसेज कर नाराजगी की वजह भी जानी, लेकिन उसके बाद राहुल ने कोई रिप्लाई नहीं किया। हार्दिक ने उम्मीद जताई थी कि चिंतन शिविर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हार्दिक ने पिछले दिनों ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपने बायो से कांग्रेस को हटा दिया था।

चिंतन शिविर में नहीं हुए थे शामिल-13-15 मई तक उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के लिए हार्दिक को भी न्योता मिला था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए थे। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत भी मिली थी। पटेल पर पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने का आरोप लगा था।

थर-थर कांपेगा दुश्मन देश, स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण

नई दिल्ली।

भारतीय नौसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होने वाली है। आज भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेश निर्मित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस बात की जानकारी डीआरडीओ की ओर से दी गई। यह सफल परीक्षण ओडिशा के चांदपुर में समुद्र तट पर किया गया। यह ऐसा पहला मौका होगा जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी नौसैनिक के एंटी शिप मिसाइल को बनाया है। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली पहली मिसाइल है। यह परीक्षण विशिष्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

साथ ही साथ यह भारतीय नौसेना का स्वदेशीकरण करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ट्विटर पर भारतीय नौसेना ने सीकिंग 42बी हेलीकॉप्टर का मिसाइल दागते वक्त का एक संक्षिप्त वीडियो जारी किया। भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार

कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के एक महीने बाद नई मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री सुरक्षा हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने के लिए अपनी समग्र युद्धक क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय नौसेना के दो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों का शुभारंभ किया था।

ममता बनर्जी ने रसोई गैस और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की

मेदिनीपुर

(पश्चिम बंगाल)। रसोई गैस और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आम आदमी को 'लूटने' का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

यहां मेदिनीपुर कॉलेज मैदान में टीएमसी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार रसोई गैस, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इज़ाफा करके आम आदमी को लूट रही है।

श्रीलंका में अभूतपूर्व संकट

समुद्र में खड़ा है पेट्रोल लदा जहाज लेकिन भुगतान के लिए नहीं हैं पैसे

कोलंबो।

श्रीलंका ने बुधवार को कहा कि उसके समुद्री क्षेत्र में लगभग दो महीने से पेट्रोल लदा जहाज खड़ा है लेकिन भुगतान करने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। हालांकि, सरकार ने कहा कि देश के पास डीजल का पर्याप्त भंडार है। आनलाइन पोर्टल न्यूजफर्स्ट डाट एलके की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली व ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने संसद को बताया कि 28 मार्च से श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में पेट्रोल से लदा एक जहाज लंगर डाले हुए है। लेकिन, उसे भुगतान के लिए श्रीलंका के पास डालर उपलब्ध नहीं है।

शिपिंग कंपनी का जहाज छोड़ने से इनकार

इसके अलावा जनवरी 2022 में पिछली खेप के लिए उसी पोत की 5 .3 करोड़ डालर की राशि भी बकाया है। मंत्री ने कहा कि शिपिंग कंपनी ने दोनों भुगतानों का निपटारा होने तक जहाज को छोड़ने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा, %यही कारण है कि हमने लोगों से अनुरोध किया कि वे ईंधन के लिए लाइन में इंतजार न करें। डीजल को लेकर कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पेट्रोल का सीमित स्टाक है और इसे आवश्यक सेवाओं, विशेष रूप से एंबुलेंस के लिए वितरित करने की कोशिश कर रहे हैं।%

ईंधन आयात के लिए 53 करोड़ डालर की दरकार

विजेसेकेरा ने कहा कि सभी फिलिंग स्टेशनों पर पेट्रोल के वितरण को पूरा करने में शुक्रवार से तीन दिन और लगेंगे। जून में श्रीलंका को ईंधन आयात के लिए 53 करोड़ डालर की जरूरत पड़ेगी। भले ही देश को भारतीय ऋण सुविधा का लाभ मिलता है, तब भी उसे दो साल पहले के प्रति माह 15 करोड़ डालर की तुलना में ईंधन खरीद के लिए 50 करोड़ डालर से अधिक की आवश्यकता होगी। श्रीलंका को ईंधन की पिछली आयात खेप के लिए 70 करोड़ डालर से अधिक राशि का भुगतान करना है।

इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे महिंदा

श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफे के नौ दिन बाद बुधवार को पहली बार संसद की कार्यवाही में शामिल हुए। उनके समर्थकों व सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के बाद उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

चीन की तरफ से राशन बांटे जाने पर आक्रोश

एएनआइ के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की कमी के बीच चीन द्वारा श्रीलंका में सूखा राशन बांटे जाने से विदेश सेवा अधिकारी संगठन (एफएसओए) में आक्रोश पैदा हो गया है। उनका कहना है कि विदेशी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए चीन दाल व चावल जैसा सूखा राशन बांटने का प्रयास कर रहा है।

गुजरात में नमक फैक्ट्री की दीवार ढहने से 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली।

गुजरात के मोर्बी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां नमक फैक्ट्री की दीवार ढह गई है। मलबे में दबने के कारण करीब 12 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंका है।

इस घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुआ कहा मोरबी में दीवार गिरने से हुई त्रासदी हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। स्थानीय अधिकारी प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मोरबी में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से दो-दो लाख रुपये दिए जाने का

एलान किया गया है। और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है गुजरात के मोरबी में एक हादसे में 12 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है। मैंने मुख्यमंत्री @Bhupendrapbjp जी से बात की है, प्रशासन राहत पहुँचाने में तत्परता से लगा है। घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुँचाकर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।

कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा का इस्तीफा

अधिकारी नहीं सुन रहे मेरी बात : घोगरा

डूंगरपुर।

पट्टे नहीं देने को लेकर डूंगरपुर एमएलए गणेश घोगरा और अधिकारियों के बीच दो दिनों से गहमा-गहमी चल रही है। एक दिन पहले एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य कर्मचारियों को पंचायत भवन में बंद करने के बाद प्रशासन ने कांग्रेस एमएलए व उनके समर्थकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद एमएलए गणेश घोगरा ने विधायक पद से इस्तीफे का पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व जिलाध्यक्ष को भेज दिया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और एमएलए गणेश घोगरा ने डूंगरपुर

सर्किट हाउस में बुधवार शाम को प्रेस कांफ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं और अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सभी के साइन होने के बावजूद लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। घोगरा ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा मैं डूंगरपुर से कांग्रेस का विधायक हूं।

सम्पादकीय

महंगाई की हाहाकार

बढ़ती महंगाई को लेकर चौतरफा हाहाकार है, मगर इसे रोकने को लेकर सरकार के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे। थोक महंगाई बढ़ कर 15.8 फीसद पर पहुंच गई है। तेल की कीमतों पर काबू पाने के प्रयास बेनतीजा साबित हो रहे हैं। सीएनजी की कीमत में फिर से दो रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। विमान ईंधन की कीमत में पांच रुपए से अधिक वृद्धि हुई है। काफी समय तक रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में इसलिए कोई बदलाव नहीं किया, ताकि बाजार में पैसे का प्रवाह कुछ बढ़े।

मगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसे ब्याज दरों में परिवर्तन करना पड़ा। उसने रेपो दरों में चालीस आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी। इससे बैंकों को कर्ज पर वसूली जाने वाली दरों में बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया। कई बैंक अपनी दरों में वृद्धि कर चुके हैं। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ब्याज दर में 0.1 फीसद की और बढ़ोतरी कर दी है। उसका मानना कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। यानी घर, वाहन आदि के लिए कर्ज लेने वालों पर बोझ कुछ और बढ़ेगा। रसोई गैस की कीमतें आम उपभोक्ता की पहुंच से दूर हो गई हैं।

खुदरा महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चे में कटौती करनी पड़ रही है। पांच खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का दम भरने वाली सरकार के सामने अब महंगाई पर काबू पाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। महंगाई का गणित कई चीजों पर निर्भर करता है। उसे किसी एक सूत्र को पकड़ कर नहीं साधा जा सकता। इसमें ईंधन की बढ़ती कीमतें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। ढुलाई महंगी होने से उभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसी के अनुसार उस पर लगने वाले करों में भी वृद्धि हो जाती है। इसी तरह हवाई यात्रा और निजी तथा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने वालों का दैनिक खर्च बढ़ जाता है।

मगर सरकार तेल की कीमत को काबू में नहीं कर पा रही। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे वैट में कटौती करें, ताकि उपभोक्ता को कुछ राहत मिल सके। मगर केंद्र सरकार कई साल से जो तेल पर ऊंचा उत्पादन शुल्क वसूल रही है, उसमें कटौती की बात नहीं की जा रही। इस वक्त पेट्रोल पर करीब छब्बीस रुपए उत्पादन शुल्क वसूला जा रहा है। यह ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी हुई है, जिसका असर हमारे यहां पड़ रहा है। मगर जब महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, तो उत्पादन शुल्क घटाने पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता।

महंगाई की मार लोगों पर इसलिए भी अधिक पड़ रही है कि उनकी कमाई नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोग अपना रोजी-रोजगार-नौकरी गंवा चुके हैं। बहुतों ने अपने भविष्य निधि से पैसे निकलवा कर भी गुजारा चलाने का प्रयास कर लिया। ऐसे में अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उनका जीना दूभर हो जाता है। खुद सरकार का दावा है कि वह देश के अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। यानी इतने लोगों के हाथ में कोई रोजगार नहीं है। इसलिए सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए समग्र रूप से विचार करने की जरूरत है।

शिक्षा, शिक्षक और मानकीकरण

नई शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करती हुई प्रतीत होती है। यह कई बदलावों को सुझाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवान शिक्षक का होना परमावश्यक मानती है। गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षक के लिए एक मानक निर्धारित करता हुआ दस्तावेज तैयार किया जाए, ऐसी संस्तुति इसी नीति नियामक दस्तावेज का योगदान है। इसी संस्तुति पर पूरे राष्ट्र के लिए एक खाका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने आनन-फानन में तैयार किया। इसमें दावा किया गया है कि इसका निर्माण सभी विद्यार्थियों को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा के न्याय संगत अवसर उपलब्ध करवाने के नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। गुणवत्ता की अवधारणा मानकीकरण की अवधारणा की पूर्ववर्ती रही होगी। यह एक समान उच्च स्तरीय व्यवहार या संसाधनों के बंटवारे को लेकर पनपी होगी। मानव व्यवहार की भिन्नता और विकट संभावनाओं के चलते मानक या मानकीकरण की अवधारणा सामाजिक बर्ताव और कौशल पर सिमट गई होगी। मशीन और मशीनीकरण के विकास ने ही मानक और मानकीकरण की अवधारणा को स्थापित किया है। माना जाता है कि एक जैसा उत्पाद और निरंतर उसी स्तर पर उत्पादन की मशीनी क्षमता ने ही मानकीकरण और उसके अपरिहार्य होने की अवधारणा को पुष्ट किया।

विकासशील देशों में शिक्षा और उसके मानकीकरण की मांग प्रायः इसके सहारे मानकीकृत समाज अथवा विकसित राष्ट्रों की कतार में पहुंचने की ललक है। शिक्षण व्यवसाय का मानकीकरण इसका पहला चरण बनता है, जिसके अनुरूप राष्ट्र के विकास में सबसे बड़े बाधक वे अध्यापक हैं जो नागरिकों को 'मानव संसाधन विकास' में पर्याप्त योगदान नहीं कर रहे हैं। अध्यापन की प्रक्रिया भी इतने मानवीय संदर्भों से होकर गुजरती है कि उसे एक मशीनीकृत अपराध नहीं माना जा सकता। विद्यार्थी, उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषायी पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, जानने के उद्देश्य और मूल्यांकन के साथ ही अध्यापक के सरोकार, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विषय, अध्यापन पूर्व प्रशिक्षण और तैयारी आदि इतने सारे सोपान हैं जिनका एक सार होना न तो संभव है, न ही वांछनीय। अध्यापन और मतांतरण का अंतर भी हमें इसके मानक तय करने से लेकर हतोत्साहित ही करेगा। अध्यापन अज्ञात से ज्ञात अथवा सहज से विशिष्ट की छात्र की ज्ञान निर्मिती यात्रा में सहायता करने की प्रक्रिया है, तो उसके मानक शायद ही किसी सार्वभौमिक चरित्र के हो सकते हैं। विकासशील देशों में शिक्षा और उसके मानकीकरण की मांग प्रायः इसके सहारे मानकीकृत समाज अथवा विकसित राष्ट्रों की कतार में पहुंचने की ललक है। शिक्षण व्यवसाय का मानकीकरण इसका पहला चरण बनता है, जिसके अनुरूप राष्ट्र के विकास में सबसे बड़े बाधक वे अध्यापक हैं जो नागरिकों को 'मानव संसाधन विकास' में पर्याप्त योगदान नहीं कर रहे हैं।

आंकड़ों के हवाले से भारतीय संदर्भ में क्रमशः पूर्व प्राथमिक स्तर पर 71.7 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर पर 40.6 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 31.3 प्रतिशत अध्यापक अपनी आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करते। इसका सीधा संबंध विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता पर पड़ता है और वे सामान्य ज्ञान, लेखन और गणना से भी वंचित रह जाते हैं। इन्हीं को आधार बना कर शिक्षक और शिक्षण के मानकीकरण की मांग की जाती है। इस आंकड़े के साथ यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि इन 'अयोग्य' अध्यापकों की संख्या का बड़ा हिस्सा निजी एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापनरत है। शिक्षा के निजीकरण के तमाम प्रयासों में ऐसा सरकारी दस्तावेज जो मानक सुनिश्चित करने के लिए हो, शायद ही निजीकरण की आर्थिकी में कारगर हो। भारत में वर्तमान में पंद्रह लाख विद्यालय हैं, जिनमें से ग्यारह लाख सरकारी हैं। 'अयोग्य' अध्यापकों का बड़ा संख्याबल उन चार लाख निजी विद्यालयों में पढ़ा रहा है जिन पर किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण अथवा अंकुश एक हस्तक्षेप की तरह उनकी निज स्वायत्तता पर हमला माना जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी इस दस्तावेज को किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा, यह भी एक भिन्न यक्ष प्रश्न है। यह दस्तावेज पुरजोर तरीके से नव नियुक्त अध्यापकों की उनके वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन की वकालत करता है। परंतु सरकारी आंकड़ों के हवाले से ही भारत में लगभग एक लाख दस हजार स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही अध्यापक है। यह अध्यापक किसको और किसके द्वारा मार्ग निर्देशित होगा, यह विकट प्रश्न है। लिंगानुपात

के आंकड़े से देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर सौ पुरुष अध्यापकों पर पचहत्तर महिला अध्यापक एवं माध्यमिक स्तर पर साठ महिला अध्यापक हैं। इन अध्यापिकाओं का मार्ग निर्देशन और तरक्की पुरुष अध्यापकों के जिम्मे हो जाएगी। यह दस्तावेज मान कर चल रहा है कि अध्यापकों में लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होते, न ही शोषण की नई पटकथा लिखे जाने की कोई संभावना है। यह आंकड़ा तो कुछ राज्यों में बहुत विकट है, उदाहरणतः बिहार में तो प्रत्येक सौ पुरुषों पर मात्र बीस महिला अध्यापक हैं। इसी तरह जातीय समीकरणों में भी सत्तावन प्रतिशत सामान्य वर्ग के आने वाले अध्यापक मात्र आठ प्रतिशत दलित अध्यापकों का बड़ी सहृदयता से ज्ञान संवर्धन एवं मार्ग निर्देशन करेंगे। यह शायद उस व्यवस्था में भले ही काम करता जिसके कोई सामाजिक-आर्थिक निष्पत्ति न हो, परंतु इस तरह के प्रयास विद्यालयों में एक नए तरह का वर्गानुक्रम एवं वर्णानुक्रम रखेंगे, यह तय है। अध्यापक अपने व्यावसायिक जीवन में कैसे बढ़ेगा, इसके निश्चय में यह दस्तावेज सुझाता है कि प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक अध्यापक होने की जगह प्रत्येक स्तर पर ही तरक्की के पदानुक्रम होने चाहिए। यह दस्तावेज प्रत्येक स्तर पर प्रगामी, प्रवीण, कुशल और मुख्य अध्यापक के क्रम को सुझाता है। उदाहरणतः यदि कोई प्राथमिक अध्यापक बनता है तो वह हमेशा प्राथमिक अध्यापक ही रहेगा। वेतनमान की चर्चा न भी की जाए, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक बनने की शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक स्तर के प्रगामी स्तर से तो भिन्न ही होगी। क्या प्राथमिक मुख्य शिक्षक का वेतन कुशल उच्च माध्यमिक अध्यापक की वेतन से अधिक होगा? ऐसे गंभीर प्रश्नों का समाधान इस दस्तावेज में देखने को नहीं मिलता। अध्यापकों की विषय वार भिन्नता को भी सिरे से नजरअंदाज करता है। उदाहरणतः प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, इतिहास इत्यादि के एक ही अध्यापक होंगे, इस परिस्थिति में वह कौन मुख्य शिक्षक होगा जो नए अध्यापक का हाथ थामेगा? क्या इन विषयों के अध्यापकों का मार्ग निर्देशन गणित अथवा विज्ञान के अध्यापकों से करवाया जाएगा? अध्यापक एवं अध्यापन के मानकीकरण से पूर्व स्कूल और ज्ञान से संस्थायीकरण के मानक तय किए जाने चाहिए।

व्यापार समाचार

टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिसर्च में खुलासा

काली कमाई छिपाने में अमेरिका सबसे ज्यादा मददगार

वॉशिंगटन।

कालेधन को छिपाने के लिए स्विट्जरलैंड दुनियाभर में लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता रहा है। हालांकि, अब स्विट्जरलैंड नहीं, अमेरिका ज्यादा मददगार बन गया है। अमेरिका में 2020 के बाद से दुनिया को फाइनेंशियल सिक्रेसी में लगभग एक तिहाई की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी एडवाजरी ग्रुप टैक्स जस्टिस नेटवर्क की ताजा रिसर्च से सामने आई है। इसके मुताबिक संपत्ति का मालिकान हक छिपाने में वित्तीय और कानूनी मदद अमेरिका से बेहतर कहीं नहीं मिलती है।

जस्टिस नेटवर्क साल 2009 से ज्यादाद के मालिकाना हक को छिपाने में फाइनेंशियल सिस्टम और कानून कितना मददगार है, इस आधार पर अलग-अलग देशों की रैंकिंग जारी

कर रहा है। ताजा रैंकिंग में इसने अमेरिका को टॉप पोजिशन पर रखा है। यह इसकी अब तक की सबसे खराब रैंकिंग है। दुनिया के सात अमीर देशों में जी-7 में से पांच- अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली फाइनेंशियल सिक्रेसी के मुकाबले आधे से अधिक ग्लोबल प्रोग्रेस रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मनी 18 मई को जी-7 देशों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। हालांकि, ट्रांसपेरेंट कानूनों को लागू करने में जर्मनी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इसलिए रैंकिंग में जर्मनी को सातवीं पायदान पर रखा गया है।

टैक्स बचाने के लिए नियम बदलता रहा है जी-7 : टैक्स जस्टिस नेटवर्क के प्रमुख रिसर्चर मोरन हरारी के मुताबिक, जी-7 धनी देशों का एक छोटा समूह है, जो फाइनेंशियल सीक्रेसी और टैक्स बचाने के वैश्विक नियमों में बदलाव करता रहता है। दशकों से ये धनी जी-7 देश अरबपतियों को लुभाते रहे हैं। इन प्रमुख देशों के टैक्स विभागों में आपस में खराब तालमेल होना है। सिर्फ अमेरिका अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल से काम करे तो दुनिया में फाइनेंशियल सीक्रेसी 40% तक कम हो सकती है और ट्रांसपेरेंसी इतनी ही बढ़ सकती है।

दरों में वृद्धि में "विलंब" को लेकर आरबीआई की आलोचना करना अनुचित : डी सुब्बाराव

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने बुधवार को कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि में विलंब को लेकर आरबीआई की आलोचना करना अनुचित है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए भविष्य का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है। इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने प्रमुख ब्याज दर बढ़ाने को लेकर बिना तय कार्यक्रम के बैठक की थी और प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अगस्त, 2018 के बाद यह पहला मौका था जब नीतिगत दर बढ़ाई गई। सुब्बाराव ने कहा कि मौद्रिक नीति का असर देर से होता है, ऐसे में दरों में हाल में की गई वृद्धि से मुद्रास्फीति तुरंत कम होने की संभावना नहीं है। दिए साक्षात्कार में कहा, "मौद्रिक हालात को मजबूत करने के लिए एमपीसी की गैर-निर्धारित बैठक जैसे जल्दबाजी में उठाए कदम से कई सवाल खड़े हुए हैं।" उनसे पूछा गया था कि बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरें पहले ही क्यों नहीं बढ़ा दीं। इस पर सुब्बाराव ने कहा, "मेरा मानना है कि यह आलोचना अनुचित है।"

एसएंडपी ने भारत का वृद्धि पूर्वानुमान घटाकर 7.3% किया

नई दिल्ली।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि के पूर्वानुमान को पहले के 7.8 फीसदी से घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया है, ऐसा बढ़ती मुद्रास्फीति और रूस तथा यूक्रेन के बीच लंबी खिंचती लड़ाई के मद्देनजर किया गया है। एसएंडपी ने अपनी 'ग्लोबल मेक्रो अपडेट टू ग्रोथ फोरकास्ट्स' में कहा कि मुद्रास्फीति का लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहना चिंता का विषय है।

5जी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे : दूरसंचार सचिव

नई दिल्ली।

दूरसंचार सचिव के राजारमन ने बुधवार को कहा कि 5जी सेवाओं की शुरुआत से नई प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त कौशल की जरूरत होगी, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजारमन ने दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएससी) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतनेट से लेकर अंतरिक्ष दूरसंचार और 5जी से लेकर ब्रॉडबैंड सेवाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। उन्होंने उद्योग को इन उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की 'पाइपलाइन' बनाने पर ध्यान देने का आह्वान भी किया। सचिव ने कहा, "उपयोग के मामलों या तरीकों में बढ़ोतरी के साथ 5जी सेवाओं में वृद्धि होगी तथा प्रौद्योगिकी की प्रकृति और क्षमता की पेशकश के चलते कौशल की एक नयी श्रृंखला भी खुलेगी।" दूरसंचार विभाग के शीर्ष अधिकारी ने 5जी की शुरुआत से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

आज का राशिफल

मेष
नौकरी से जुड़े जातकों को किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सावधान रहना होगा। यदि किसी से धन का लेन देन करें, तो उसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा अवश्य करें।

वृषभ
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको किसी भी विपरीत स्थिति को संभालने के लिए गंभीरता से काम लेना होगा। विद्यार्थियों को भी आज परीक्षा में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे।

मिथुन
आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको साझेदारी में किसी नए व्यवसाय को करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा।

कर्क
सायंकाल के समय आप किसी व्यवसाय की डील को फाइनल करने के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों को आज कुछ जनसभाएं करने का मौका मिलेगा।

सिंह
आज का दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, जिनके कारण आप अपने खर्चो पर भी लगाम लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में उथल-पुथल बनी रहेगी।

कन्या
आपको कार्यक्षेत्र में भी संभल कर रहना होगा, नहीं तो कोई वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सायंकाल का समय आप अपने किसी परिजन से संतान के विवाह में आ रही समस्या पर बातचीत कर सकते हैं।

तुला
आज का दिन आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। संतान की कुछ फरमाइशें भी आज पूरी करते नजर आएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत करने का रहेगा, तभी वह परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे।

वृश्चिक
आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे लोग किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी।

धनु
नौकरी से जुड़े जातकों को अपने अधिकारियों के कठोर व्यवहार के कारण कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। सायंकाल के समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं।

मकर
जीवनसाथी से आप संतान की कुछ समस्याओं को साझा करेंगे, जिनका समाधान आप मिलकर खोजेंगे। आपको अपने लम्बे समय से रुके हुए कानूनी कार्य की सुध बुध लेनी होगी, नहीं तो वह लंबा खिंच सकता है।

कुंभ
परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अक्समात गिरावट के कारण आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से बातचीत करके आप अच्छा महसूस करेंगे।

मीन
आपको जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को लेने से बचना होगा। आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन जिन्हें आपको दूर करना होगा, तभी आप किसी काम पर फोकस कर पाएंगे।

अधिकारियों पर भड़के प्रधान, पं.स. सदस्य व सरपंच

प्रस्तावों पर अमल नही करने व बैठकों मे अधिकारियों के नही आने से बढ़ी नाराजगी

हंगामेंदार रही पंचायत समिति की बैठक

शौकत खान

डेगाना(नागौर डेली न्यूज)। पंचायत समिति डेगाना की बुधवार को साधारण सभा बैठक हंगामेदार हुई। प्रधान सुनिता चौधरी की अध्यक्षता मे आयोजित इस बैठक में सरकारी विभागों के सक्षम अधिकारियों के नहीं आने ओर अपने जुनियर अधिकारियों को भेज दिये जाने से प्रधान सुनिता चोयल सहित सभी पंचायत समिति के सदस्य ओर सरंपचों ने गहरी नाराजगी प्रकट की।

बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाही करने के लिए विकास अधिकारी को कहा गया। बैठक में सर्व प्रथम बिजली की समस्या पर मुद्धा उठा, जिसमें पिछले एक साल से सदस्यों द्वारा उठाई जन समस्याओं का आज तक निवारण करना तो दूर संतोषजनक जबाब तक नहीं देने पर सदस्यों ने सदन का अपमान बताया ओर प्रधान सुनिता चोयल ने सदन में मौजूद जेईएन को लताड़ा। सदस्य हनुमान जाजुन्दा, सुखराम धूण, हनुमान प्रसाद, राजेन्द्र ईनाणिया, जिला परिषद सदस्य मनीष चौधरी, सरपंच कैलाश महिया, महादेव सिरासना आदि ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाही अमल में लाने का प्रस्ताव लिया। सदस्यों ने बताया की चांदारूण में पिछले 6 महीने से पानी नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से लवादर गांव में ओर तामडोली की स्कूल में पिछले एक साल से पानी नहीं आ रहा है। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग पर घटिया निर्माण सामग्री से पेचवर्क करने, नियमित रूप से पेयजल सप्लाई नही होने, नहरी जल प्रदाय योजना के तहत खोदे गये खड्डों में सीमेंट की जगह मिट्टी से भरने के मामलों की जांच कराने के लिए सदस्यों ने प्रस्ताव लिये।

ये रहे मौजूद : इस अवसर पर प्रधान सुनिता चोयल, विकास अधिकारी भंवराराम कालवी, बीसीएमओ डॉ. रामकिसोर सारण, तहसीलदार छोटूराम, एईएन दिलीप लांबा, शिक्षा, सडक, नहरी पानी, बिजली विभाग के अधिकारी, जिला परिषद सदस्य मनीष चौधरी, पंचायत समिति सदस्य हनुमान जाजुन्दा, सुखराम धूण, हनुमान प्रसाद, राजेन्द्र ईनाणिया, सरपंच शिवलाल डिया, किशनसिंह खैरवा, पुरखाराम मेघवाल जालसु, केलाश महिया जालसु नानक, शिवप्रताप सिंह ईड़वा, महादेव सिरासना, जस्साराम सहित सदस्य मोजूद रहे।

सदन की बैठकों को अधिकारी बना रहे मजाक : साधारण सभा की बैठकों में नहीं आने तथा सदन के सदस्यों द्वारा जनहित की उठाई समस्याओं को बैठक दर बैठक प्रस्ताव लेने के बाद भी निराकरण करना तो दूर संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा संतोषजनक जबाब तक सदन को नहीं देने पर सदस्य हनुमान जाजुन्दा ने इसे सदन का अपमान बताते हुये लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर कार्रवाही करने की मांग की। जाजुन्दा ओर सुखराम धूण ने बताया कि बैठकों में सदस्य चाय नाश्ता करने नहीं आते जनता की समस्या लेकर आते है, लेकिन सरकारी अधिकारी सदन के प्रस्तावों पर कोई अमल नहीं करते। जनता बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से परेशान है। कोई सुनने वाला नहीं है। इस पर प्रधान सुनिता चौयल ने मामले पर संज्ञान लेने का पुरा आश्वासन दिया।

डेगाना में चल रही फर्जी पट्टा बनाने वालों की दुकानें

पंचायत समिति की बैठक मे हजारों रूपये लेकर सरपंचों के फर्जी हस्ताक्षरों कर गौचर के फर्जी पट्टे बनाने का मुद्धा गरम रहा है। जालसु सरपंच केलाश महिया, जिला परिषद सदस्य मनीष चौधरी, हनुमान जाजुन्दा, सुखराम धूण आदि ने बताया की डेगाना तहसील परिसर मे सरपंचों ओर ग्राम सेवकों के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रतिबंधित गौचर भूमि के फर्जी पट्टे बनाकर दिये जा रहे है। जालसू सरपंच ने सदन मे आरोप लगाया की डेगाना मे कुछ लोगो द्वारा फर्जी दुकानें चलाकार भोले भाले ग्रामीणों को 35 हजार तक रूपये लेकर फर्जीवाडा से गौचर भुमि के पट्टे बनाकर बेचे जा रहे है। जिन्हे तहसीलदार द्वारा भी बिना किसी जांच के फर्जी पट्टों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मनीष चौधरी ने बताया की ऐसे फर्जी पट्टों से लोग बेंकों से लाखो रूपयों का ऋण लेकर भ्रष्टाचार किया जाता है। ऐसे गिरोह मे तहसील के अधिकारी भी मिले हुये है। सरपंच केलाश महिया ने बताया की उनकी ग्राम पंचायत मे आठ ऐसे फर्जी पट्टे सामने आये है जिन पर सरपंच ग्राम सेवक के फर्जी दस्तखत ओर गलत नाम है। जिनका तहसील कार्यालय मे बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। लोगो ने ऐसे पट्टों से बेंकों से लाखो रूपयों का ऋण भी उठा लिया। सदस्य हनुमान जाजुन्दा ने पिछले सालों मे रजिस्ट्रेशन किये पट्टों की जांच करने की मांग की। सदन मे बताया की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ऐसे हजारों फर्जी बना दिये है। ओर आज दिन भी लगातार फर्जी पट्टे बन रहे है। सदस्यों ने पट्टों का रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व संबधित सरपंच से पट्टे का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव लेकर तहसीलदार को निर्देशित किया ओर मामले की जांच कराने की मांग की।

नागौर में नया जिला बनाने को सात दिन में मांगे प्रस्ताव

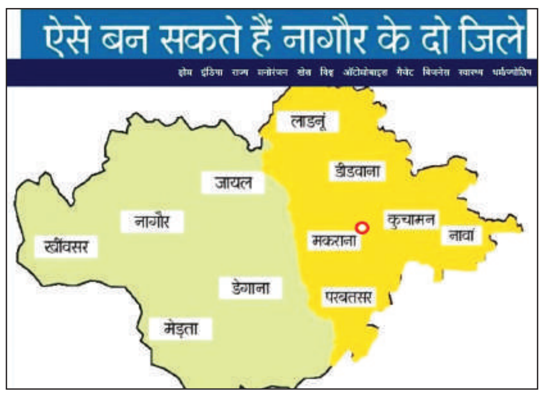

जिला कलक्टर ने एडीएम व एसडीएम की बैठक लेकर दिए निर्देश

नागौर(नागौर डेली न्यूज) :

क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के पांचवें सबसे बड़े जिले नागौर का पुनर्गठन कर दो जिले बनाने की मांग अब पूरी होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने जिले के सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारियों को नवीन जिला सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव, ज्ञापन व मांग पत्र प्राप्त कर 7 दिन में जिला मुख्यालय भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

चार दिवसीय धार्मिक बस यात्रा हुई रवाना

श्यामसुन्दर प्रजापत

मीठड़ी(नागौर डेली न्यूज) : मीठड़ी कस्बे के गणगौरी चौक स्थित जाल का बालाजी मंदिर के सामने से बुधवार को प्रात: 8.15 बजे रावणा राजपूत विकास समिति मीठड़ी के तत्वावधान में एक धार्मिक चार दिवसीय प्रथम बस यात्रा रवाना हुई। यात्रियों ने रवाना होने से पूर्व बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। 50 पुरुष व महिला यात्रियों से भरी बस को पूर्व वार्ड पंच किशनसिंह सौलंकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दलपतसिंह सोलंकी ने बताया कि यात्रियों को ओसियां माताजी, रामदेवरा, ओम बन्ना, गाजन माताजी, खिवज माताजी, भीनमाल, माउंट आबू, अम्बाजी, पुष्कर, खुंडियास आदि धार्मिक स्थलो का दर्शन कर लौटेगा। इस दौरान किशन सिंह सोलंकी, राजेंद्र सिंह कच्छावा, दलपत सिंह, हेम सिंह, सत गोपाल गौ चिकित्सा लय अध्यक्ष भंवरसिंह सोलंकी, झब्बरसिंह, विजेन्द्र सिंह, महेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, गोकुल सिंह, दीपेन्द्र सिंह सहित मातृ शक्ति मौजूद थी।

दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति, ऑनलाइन होंगे विद्युत कनेक्शन के आवेदन

अबूबकर बल्खी

लाडनूं(नागौर डेली न्यूज) : अजमेर डिस्कॉम में उपभोक्ताओं की सुविधा एवं निगम के कामकाज में तेजी लाने के साथ साथ बिचौलियों की व्यवस्था खत्म करने के लिए नए कनेक्शन लोड, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन आदि कार्यों के लिए उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। निगम के सहायक अभियंता लालचंद आंवला ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के एम.डी. एम.एस निर्वाण ने निगम अभियंताओं को उनके कार्यालयों की लंबित पत्रावलियां आगामी 6 दिनों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सीआरएम प्लस के द्वारा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। 20 मई के बाद प्राप्त ऑफलाइन आवेदन की फाइलों को भी ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से उपभोक्ताओं को उसकी फाइल के मूवमेंट की सभी जानकारी मैसेज के जरिए प्राप्त होगी इससे कनेक्शन की पेंडेंसी आदि की जानकारी भी ऑनलाइन ही मिल सकेगी।

एक बार में ही देनी होगी दस्तावेजों की सूची : अजमेर डिस्कॉम के शहरी कार्यालय जेईएन राजकुमार तुंगरिया ने बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ उसे वांछित दस्तावेजों की सूची एक बार में ही देने के लिए निर्देश मिले हैं। इससे आवेदक एक बार में ही आवेदन पूर्ण कर जमा करा सके। आवेदन पत्र का प्रारूप चेक लिस्ट सहित डिस्कॉम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा उपभोक्ता डिस्कॉम की वेबसाइट पर नए कनेक्शन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति

विद्युत निगम में प्राय: घर के बिजली कनेक्शन, अस्थाई कनेक्शन, लोड बढ़ाना, लोड – घटाना, नाम परिवर्तन, कनेक्शन ट्रांसफ,र कनेक्शन शिफ्टिंग, श्रेणी परिवर्तन आदि कार्यों के लिए कार्यालयों में आवेदन करने पर आवेदक को जरूरी व आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण विवरण एक बार में नहीं दिया जाता इसके अभाव में आवेदक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं जिससे कार्य मे देरी भी होती है एवं बिचौलियों को बढ़ावा मिलता है वंही अब आवेदन ऑनलाइन होने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।

कुचामन क्षेत्र के गांवों में हुए प्याज की फसल के नुकसान की विशेष गिरदावरी शुरू

सद्दाम रंगरेज

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : देश-प्रदेश में प्रसिद्ध कुचामन क्षेत्र के मीठे पानी के प्याज की फसल में इस बार भीषण गर्मी से हुए नुकसान का आंकलन करने हेतु विशेष गिरदावरी की जा रही है। पिछले दिनों क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधी मंडल प्याज की फसल के नुकसान के मुआवजे को लेकर जिला कलक्टर नागौर जिला प्रमुख सांसद व उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी से मिला था, जिस पर जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार द्वारा क्षेत्र के सभी पटवार सर्किल में पटवारियों द्वारा विशेष गिरदावरी की जा रही है। पिछले दिनों नगवाड़ा सरपंच मनोज लोरा द्वारा अवगत करवाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्याज की फसल का सर्वे कर माना कि इस बार भीषण गर्मी की वजह से फसल 50-70 प्रतिशत तक नुकसान हो गया है।

श्यामसुंदर मंत्री के प्रांतपाल निर्वाचित होने पर गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति ने किया स्वागत

सद्दाम रंगरेज

कुचामनसिटी(नागौर डेली न्यूज) : लायंस क्लब अंतरराष्ट्रीय प्रांत 3233 ई-2 के प्रांतपाल (24-25) के उदयपुर में हुए चुनाव में लायंस क्लब कुचामनसिटी के वरिष्ठ लॉयन व गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय महासचिव श्यामसुंदर मंत्री विजयी हुए। लायंस क्लब के प्रांतीय सीईओ (रक्तदान) व गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति कुचामन के अध्यक्ष श्यामसुंदर सैनी ने बताया कि इस चुनाव में प्रांत के 192 क्लब के राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लगभग 6000 सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में 594 लोगों के मत थे, जिसमें से 556 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें से मंत्री को 294 वोट मिले। उल्लेखनीय है कि लायंस क्लब कुचामनसिटी 50 वर्ष पुराना क्लब है, जिसमें कुचामन के किसी सदस्य को पहली बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला तथा इसमें मंत्री विजयी हुए। यह विजय लायंस क्लब के साथ ही गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति एवं कुचामन नगर के लिए भी गौरव की बात है।

सी.आर.चौधरी सहित अनेक लोगो ने किया स्वागत : समिति के सचिव परमानंद अग्रवाल ने बताया कि मंत्री के उदयपुर से विजयी होकर कुचामन आने पर समिति द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन रामेश्वरम न्यू कॉलोनी में किया गया, जिसमें समिति के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री सी.आर. चौधरी, कुचामन इकाई के संरक्षक पूर्व नगरपालिका चेयरमैन नटवरलाल वक्ता, कुचामन इकाई अध्यक्ष श्याम सुंदर सैनी, सचिव परमानंद अग्रवाल, सह-सचिव अनंत तिवारी, उपाध्यक्ष मुरलीधर गोयल, वरिष्ठ सदस्य सत्यनारायण मोर, राजू राम नेहरा, महिला प्रभारी हेमा गट्टानी, पूर्व विधायक हरिश्चंद्र कुमावत, न्यू मॉडल स्कूल के संस्थापक व खारिया सरपंच देवीलाल कुमावत, समाज सेवी ज्ञानाराम रणवा, प्रदीप गट्टानी एंव पूसाराम कुमावत आदि ने मंत्री का माला-साफा व दुपट्टा पहना कर स्वागत किया व एक दूसरे का मुँह मीठा करा कर खुशियां मनाई।

मेड़ता को जिला बनाने की फिर उठी मांग

मेड़ता(नागौर डेली न्यूज) :

मेड़ता को पुन: जिला बनाने के लिए सामाजिक सरोकार से जुड़े नागरिकों ने मेड़ता जिला पुन गठन संघर्ष समिति मेरता मेड़ता शहर के तत्वावधान में मेड़ता के नागरिकों व समिती सदस्यों द्वारा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य सरकार के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी मेड़ता शैतान सिंह राजपुरोहित को आज सौंपा। ज्ञापन में मेड़ता को जिला बनाने के लिए जो भी अहर्ता है उनका विस्तृत विवरण दिया और मांग की गई कि इन सभी योग्यताओं के मध्य नजर रखते हुये मेड़ता को पुन: जिला बनाया जाना सर्वथा न्यायोचित है। रियासत काल में सन 1949 से पहले मेड़ता में सभी जिला स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध थी। मेड़ता सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक व्यापारिक भौगोलिक पर्यटन यातायात सभी दृष्टि से जिले के काबिल जगह है। इसलिए प्रस्तावित जिलों में मेड़ता का भी चयन किया जाकर अविलंब मेड़ता को जिला बनाया जाना चाहिए।

बालिका विद्यालय को मिला खेल मैदान

अ.रहमान देवड़ा

मूण्डवा(नागौर डेली न्यूज) : आजादी से पूर्व सन् 1939 में यहाँ के चांडक परिवार ने बालिका शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला की नींव रखी। आजादी के पहले ही बालिका शिक्षा की चिंता करना चांडक परिवार की दूरदृष्टि और जन्मभूमि के प्रति लगाव को दर्शाता है। कालान्तर में विद्यालय जब उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ तो शहर में ही जमीन लेकर सारडा परिवार ने भवन बनाकर सरकार को गिफ्ट किया। धर्म नगरी मूंडवा की पहचान इसी दानवीरता के कारण उच्चता को प्राप्त होती है।

90 घंटे बाद हुआ जयपाल पुनिया के शव का पोस्टमार्टम, 7 घंटे चली कार्यवाही

गोली के मेटल को ढूंढने में लग गए 5 घंटे

पुष्प वर्षा कर शव वाहन को किया पैतृक गांव के लिए रवाना

मोतीसिंह चौधरी सहित चार अन्य आरोपियों को किया न्यायालय में पेश

हितेश रारा

नावांसिटी(नागौर डेली न्यूज) : जयपाल पुनिया हत्याकांड में उपमुख्य सचेतक एवं नावां विधायक महेन्द्र चौधरी के बड़े भाई मोतीसिंह चौधरी पुत्र हनुमान सिंह चौधरी के अलावा रिश्तेदार कुलदीप सिंह पवेरा नागंल हरियाणा, फिरोज खान पुत्र भंवरू खां नावां, हनुमान सैनी पुत्र किशनराम निवासी मथानिया, हारून कायमखानी पुत्र गफूर खान निवासी वार्ड नम्बर 14 नावां को बुधवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। इससे पूर्व 90 घंटे बाद शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान हॉस्पिटल की सुरक्षा चाक चौबंद रही। मेडिकल बोर्ड से सर्वप्रथम शव का एक्स-रे करवाया गया ताकि शव में गोली लगने के मेटल की खोज कर सके, लेकिन मेडिकल बोर्ड को सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में स्थित एक्स-रे मशीन में मेटल की खोज नहीं हो सकी। हॉस्पिटल में उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट एवं तहसीलदार ला एण्ड आडर के लिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की विशेष रूप से देखरेख कर रहे थे। इस दौरान एसएफएल टीम को नावां के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में बुलाया गया। शव का डिजीटल एक्स रे जांच करने से गोली के मेटल की खोज की गई। इसके पश्चात ही शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ जो 7 घंटे चला। इसके बाद शव को उनके पैतृक गावं चुरू के राजगढ के गगड़वार गाव में भेज दिया गया।

हॉस्पिटल में भाजपा व आरएलपी नेताओं का लगा रहा जमावड़ा : नमक उद्यमी जयपाल पुनिया की हत्या के मामले में भाजपा एवं आरएलपी के नेताओं का दिन भर जमावड़ा रहा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी, पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, पूर्व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हरीश चन्द्र कुमावत, आरएलपी के विधायक नारायण बेनिवाल, ज्ञानाराम रणवां, खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल सहित अनेक नेता हॉस्पिटल में डटें रहे। इसके अलावा राजेश गुर्जर, नावां भाजपा मण्डल के अध्यक्ष प्रकाश योगी, उपाध्यक्ष आनन्दी लाल कुमावत, जगदीश छापोला, चुन्नी लाल सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

ज्यूस पिलाकर तुड़वाया कुमावत का अनशन

भाजपा के वयोवृद्ध नेता हरीशचन्द्र कुमावत का मंगलवार की रात्रि आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद ज्यूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। इस दौरान आरएलपी सुप्रिमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सर्वप्रथम हरीश कुमावत ने ही इस जंग की शुरूआत की थी और आज हम सबने उनका साथ देकर आरोपियों को गिरफ्तार करवाया है।

मार्बल फर्म के प्रमाण पत्रों का किया विमोचन

मोहम्मद शहजाद

मकराना(नागौर डेली न्यूज)। संगमरमर व्यापार मण्डल बाईपास रोड मकराना के कार्यालय में अध्यक्ष अब्दुल रहीम सिसोदिया की अध्यक्षता में बुधवार को मकराना मार्बल व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मकराना मार्बल व्यापारियों को दिए जाने वाले प्रशस्ति प्रमाण पत्र का विमोचन किया गया।

अध्यक्ष अब्दुल रहीम सिसोदिया ने बताया कि जो भी मकराना मार्बल व्यापारी शत प्रतिशत मकराना मार्बल का कारोबार करते हैं एवं मकराना मार्बल को प्रोत्साहित करते हैं, उन सभी व्यापारियों को संगमरमर व्यापार मण्डल बाईपास रोड मकराना द्वारा एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 23 मई सोमवार से की जाएगी। वहीं बैठक में दूसरा निर्णय लिया गया की गुरुद्वारा से घाटी चौराहा तक सड़क के मध्य बने डिवाइडर को हटवाने व डिवाइडर के मध्य स्थित विद्युत पोल सेफ्टी के लिए राउंड अप कर के मार्बल व्यापारियों के सहयोग से व्यापारिक फर्मो के नाम लिखवाए जाएंगे जिससे रोड सुंदर दिख सके और गाड़ियों को मार्बल गोदाम में लगाने में होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। इस दौरान उपाध्यक्ष जेनुल आबदीन चौधरी, सचिव मोहम्मद शरीफ राठौड़, कोषाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार बैहलीम, पूर्व सचिव अब्दुल अजीज सिसोदिया, मार्बल व्यापारी जहीर अहमद भाटी, हाजी हयात गैसावत, पार्षद अब्दुल हलीम रान्दड, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद हुसैन राठौड़, अब्दुल रहमान खत्री, अल मदद विकास सेवा समिति अध्यक्ष हाजी मुगय्यर आलम गैसावत, मोहम्मद अफजल राठौड़, अब्दुल समद खत्री, रूपचंद सैन, गंगाराम तानाण, अब्दुल करीम सिसोदिया सहित कई मार्बल व्यापारी उपस्थित थे।

कनिका शर्मा को पुरस्कार में मिली स्कूटी

मोहम्मद शहजाद

मकराना(नागौर डेली न्यूज)। शहर के सुभाष नगर में स्थित मारवाड़ मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा कनिका शर्मा पुत्री गिरधारी लाल शर्मा का राजस्थान सरकार मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में चयन हुआ। इस अवसर पर संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में संस्था संरक्षक ध्रुव लाल छंगाणी ने बताया कि छात्रा कनिका शर्मा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा सामान्य वर्ग विज्ञान संकाय में शत प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसके आधार पर छात्रा को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। इस अवसर पर संस्था निदेशक जगदीश प्रसाद छंगाणी, बाबूलाल बिश्नोई, रंजीत कुमार गुप्ता, संजय ठाकुर, आसीफ अली, विजय सिंह शेखावत सहित संस्था परिवार ने छात्रा को माला व साफा पहनाकर बधाई देते हुए मुँह मीठा करवाकर उत्साहवर्धन किया।

इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से छात्रा को उपहार स्वरूप स्मृति चिह्न देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर छात्रा के दादा केदार लाल शर्मा ने विद्यालय की छात्राओं को कनिका शर्मा से प्रेरणा लेते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी।

चार वार्डों के लिए आयोजित हुआ शिविर

जुगल किशोर शर्मा

परबतसर(नागौर डेली न्यूज) : प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत बुधवार को चार वार्डो का अभियान भैंरू बाबा मन्दिर चौक में आयोजित किया गया, जिसमें बुधवार को नगेन्द्र चौधरी अधिशाषी अधिकारी एवं पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश सैन, उपाध्यक्ष रामनिवास दिवाकर, कनिष्ठ लिपिक मनोज चौहान, अजय माली कनिष्ठ लिपिक द्वारा 69-ए के तहत 01 पट्टा, 1 निर्माण स्वीकृति एवं पांच जन्म प्रमाण पत्र जारी किये गये।

पाईप लाइन क्षतिग्रस्त कर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ जलदाय विभाग ने कराया मुकदमा

डेगाना(नागौर डेली न्यूज)।

डेगाना के ग्रामीण क्षैत्रों मे कुछ टैंकर चालकों ने विभाग की पाईप लाईन को जगह-जगह से क्षतिग्रस्त कर नहर का मीठा पानी रोजाना भारी मात्रा में चोरी करने एवं सरकारी पानी को मंहगी रेट पर लोगो के अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ पुलिस मे मुकदमा दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कर्रवाही करने की मांग की है। जलदाय विभाग सहायक अभियंता दिलीप लाम्बा ने जानकारी देकर बताया की डेगाना पंचायत समिति के ग्राम देवलामादा, सिरासना, उदियास आदि गांवों में कापडीयावास जल प्रदाय योजना से विभागीय नलकूप द्वारा पाईप लाईन के जरिये कापडीयावास, खेड़ूली, डाबरयानी, जावली, रेवा, देवलामादा होते हुए डेगाना के ग्राम सिरासना, उदियास इत्यादी में पेयजल सप्लाई की जाती है। इस 250 एमएम की लाइन में कुछ शरारती लोगों द्वारा रात में अंधेरे का फायदा उठाकर पाईप लाईन को कई जगहों से तोड कर अवैध रूप से पानी की चोरी कर टेंकर भरे जाते है।

तेजाजी मन्दिर निर्माण को लेकर बांटे पीले चावल

रमेश जाजड़ा

जायल(नागौर डेली न्यूज) : जन जन के आराध्य लोक देवता खरनाल में होने वाले वीर तेजाजी महाराज के मन्दिर निर्माण कार्यक्रम को लेकर वीर तेजा मन्दिर कमेठी ओर हरियाणा के चौटाला परिवार का प्रतिनिधि मण्डल द्वारा बुधवार को जायल के लीलण चौक स्तिथ वीर तेजाजी मन्दिर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा समित सदस्यों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान समिति सदस्यों ने 10 जून को होने वाले मन्दिर निर्माण कार्यक्रम में पहुचने को लेकर पिले चावल बांटे गये। निमंत्रण यात्रा में शामिल बिट्ठू नेण, सुखराम खुड़खुड़िया, मनीराम गोदारा, सरपंच शिवकरण धोलिया, अर्जुनराम, प्रतापराम आदि सदस्यों का स्वागत किया गया। समिति के रणजीत धोलिया ने कहा कि 10 जून को खरनाल में विशाल तेजाजी महारज के नीव का महूर्त होगा, जिसमें अधिक से अधिक पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच रामकरण लोमरोड़, मोतीराम लोमरोड़, जगदीश लोमरोड़, मोहनराम नेतड़, पंचायत समिति सदस्य हनुमानराम लोमरोड़, रामकरण चौधरी, मनीराम लोमरोड़, रामकिशोर लोमरोड़, राजेश रलिया सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

डेगाना नगरपालिका के मास्टर प्लॉन में गांवों को जोड़ने से ग्रामीणों में रोष

एसडीएम को ज्ञापन देकर नगरीय सीमा से बाहर करने की मांग

शौकत खान

डेगाना(नागौर डेली न्यूज)। डेगाना शहर के मास्टर प्लॉन के नगरीय क्षेत्र से कई पास के गांवो को हटा कर दूसरे नये गांव जोड़ने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं व गांव वासियों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता रामचंद्र डूडी ने बताया की मास्टर प्लान में डेगाना के आसपास के गांवों को सम्मिलित करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया ओर दूसरे गांवों को मनमर्जी से जोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने नाराजगी प्रकट की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में जानकारी दी की चांदारुण, बाजियासर, देवनगर व रावलियावास के समस्त क्षेत्र को मास्टर प्लान में जोड़ा गया है, जो की उचित नहीं है। बुधवार को ग्राम चांदारुण से सैकड़ो की संख्या में ग्रामीणों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया ओर कहा कि अगर मास्टर प्लान से चांदारुण गांव जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है नगरपालिका की विकास योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता है। गांव की 90 फीसदी जनता मजदूरी व कृषि पर निर्भर हे। अगर नगरपालिका द्वारा ऐसे गांवो को मास्टर प्लान मे जोड़ा जायेगा तो इन पर आर्थिक बोझ बढ़ जायेगा। इस अवसर पर अनिल कुमार जोशी, पंचायत समिति सदस्य डॉ. हनुमान जाजूंदा, सुखराम धूण, रामचंद्र डूडी, युनुस खाँ, जगदीश तिवारी, रामनिवास जाजूंदा, देवीलाल, बंशीलाल, दिनेश, वासु स्वामी, ओमनाथ, सुरेश, प्रवीण, सीताराम, मोहनसिंह, भंवरलाल धोजक, केलाश, वीरेंद्र रिणवा, ओमप्रकाश, हनुमान भाकर सहित पार्षद अंजू शेखावत, चोथी देवी ग्रामीण मौजूद रहे।

मकराना को जिला बनाने की मुहिम हुई तेज

मोहम्मद शहजाद

मकराना(नागौर डेली न्यूज)। शहर के होटल गणगौर में मकराना विकास समिति की एक बैठक समिति अध्यक्ष नितेश कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर के द्वारा नागौर जिले में नया जिला बनाने के लिए सभी संगठनों को प्रस्ताव के लिए कहा है जिसका समय 1 सप्ताह यानी 7 दिन का रखा गया है। मकराना विकास समिति ने बुधवार को मीटिंग में सर्व सहमति से निर्णय लिया कि मकराना क्षेत्रफल, शैक्षणिक, टेक्स, चिकित्सा, मार्बल व्यापार, हैंडीक्राफ्ट, माइनिंग सहित अन्य क्षेत्र में मकराना जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है। इस हेतु सर्व समाज एवं सामाजिक संगठनों की गुरुवार 19 मई शाम 4 बजे एक सामूहिक मीटिंग रखी गई है। जिसमें मकराना को जिला बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जिसके लिए सभी धार्मिक, सामाजिक, वाणिज्य, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यापारिक, माइनिंग एसोसिएशन की राय लेकर सामूहिक प्रयास की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत, कोषाध्यक्ष राजीव सोलंकी, सजाउद्दीन गेसावत (लाडू जी), रामस्वरूप सोलंकी, दिलीप सिंह दिलढाणी, बजरंग सिंह मंडोवरी, सह सचिव गंगाराम मेघवाल, गिरधर पलोड़, मोहम्मद इरशाद सिसोदिया, विक्रम सिंह शेखावत, रणजीत सिंह राजपुरोहित सहित अन्य उपस्थित रहे।

शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने पार्षद शक्तिसिंह ने उपसभापति को सौंपा ज्ञापन

मोहम्मद शहजाद

मकराना(नागौर डेली न्यूज़)। नगर परिषद मकराना के विभिन्न वार्डो व मुख्य स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने नगर परिषद के वार्ड 34 के पार्षद शक्ति सिंह चौहान ने बुधवार को उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर आम नागरिकों व दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जिसके शहर के मुख्य रास्ते संकड़े एवं छोटे हो गये है। शहर के मुख्य रोड़ बाईपास तिराहा से गौड़ाबास, जयशिव चौक होते हुए रेलवे स्टेशन तक, जयशिव चौक तिराहा से चारभुजा मंदिर होते हुए सदर बाजार, धूतों का चौक से मेवलिया बड़ तक, सिनेमा गली के अन्दर दुकानदारों द्वारा, दुकानों के आगे सामान रखकर व अपनी स्वामित्व भूमि से अधिक पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक एंव संपादक सद्दाम द्वारा नेशनल प्रिंटर्स, लोहा मंडी, डीडवाना से मुद्रित तथा घाटी कुआँ, छीपा मोहल्ला, कुचामनसिटी, जिला नागौर (राज.) से प्रकाशित। मोबाइल नम्बर 7737211664 Email-nagaurdaily0@gmail.com